ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, सोमवार 05 जनवरी 2026

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 242

डूंगरपुर में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का अवकाश, जिला कलक्टर ने आदेश जारी किया

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 6 जनवरी से 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र, मां बांडी केंद्र और सरकारी व निजी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई स्थगित रहेगी।

कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा। विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और मां बांडी केंद्रों के समस्त कर्मचारी सामान्य समयानुसार कार्यरत रहेंगे और किसी भी परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा।

जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी या निजी विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कंपनी BCCL का IPO 9 जनवरी को खुलेगा:एक शेयर की कीमत 23; कम से कम 13,800 का निवेश करना होगा

24 न्यूज अपडेट

कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) अपना पहला IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 21 से 23 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह इशू 9 जनवरी 2026 को खुलेगा और 13 जनवरी को बंद होगा।

BCCL एक सरकारी कंपनी है और स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कोयले (कोकिंग कोल) के उत्पादन में भारत में नंबर-1 पर है। इसे 2014 में 'मिनी रत्न' का दर्जा मिला था। इस आईपीओ के जरिए प्रमोटर कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

निवेशकों को कम से कम 600 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी। ऊपरी प्राइस बैंड 23 के हिसाब से एक लॉट के लिए न्यूनतम 13,800 निवेश करने होंगे।

एंकर इन्वेस्टर्सः बड़े निवेशकों के लिए बिडिंग 8 जनवरी को खुलेगी।

इशू बंद होने की तारीखः 13 जनवरी 2026।

कर्मचारियों को छूटः पात्र कर्मचारियों को हर शेयर पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा।

BCCL के इस आईपीओ का कुल साइज 46.57 करोड़ शेयरों का है। यह पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' है। यानी, आईपीओ से मिलने वाला सारा पैसा प्रमोटर कोल इंडिया लिमिटेड के पास जाएगा। कोल इंडिया इस इशू के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के निजी आवास पर हमला, एक संदिग्ध हिरासत में

24 न्यूज अपडेट

वॉशिंगटन/सिनसिनाटी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड (जेडी) वेंस के ओहायो राज्य के सिनसिनाटी शहर में स्थित निजी आवास पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क सीएनएन के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

अधिकारियों के अनुसार, रविवार देर रात करीब 12:15 बजे उपराष्ट्रपति के आवास के आसपास एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी घर के भीतर प्रवेश करने में सफल नहीं हो सका। राहत की बात यह रही कि जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि यह घटना उपराष्ट्रपति या उनके परिवार को निशाना बनाकर की गई सुनियोजित कार्रवाई थी या फिर किसी अन्य कारण से की गई तोड़फोड़। मामले की गंभीरता को देखते हुए संघीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। मीडिया की ओर से व्हाइट हाउस और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से प्रतिक्रिया मांगी गई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पिछले एक सप्ताह से सिनसिनाटी में थे, हालांकि वह रविवार दोपहर शहर से रवाना हो चुके थे। बताया जा रहा है कि वेंस ने इस आवास को लगभग 14 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और यह संपत्ति बड़े भू-भाग में फैली हुई है।

अमेरिका के संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जेपीएल-4 की सफलता के उपलक्ष्य में सेन्ट्रल युवा समिति का स्नेह मिलन कार्यक्रम

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सिन्धी सेन्ट्रल युवा सेवा समिति द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित झुलेलाल प्रीमियर लीग (जेपीएल-4) की सफलता के उपलक्ष्य में समिति से जुड़ी 32 युवा संस्थाओं के सदस्यों का स्नेह मिलन कार्यक्रम शिकारवाड़ी स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी सक्रिय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और आगामी कार्यक्रमों को और अधिक भव्य एवं सफल बनाने पर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष विजय आहूजा ने बताया कि जेपीएल-4 को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों का विशेष धन्यवाद किया गया। महासचिव मुकेश खिलवानी ने बताया कि समाज की महिलाओं के लिए आगामी 14 और 17 जनवरी को रानी विलेज में खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपाध्यक्ष राजेश खत्री ने बताया कि इन महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। स्नेह मिलन कार्यक्रम की सफलता में समिति के कई सदस्यों का विशेष योगदान रहा। इसमें मनोज कटारिया, मनीष डेमला, मुकेश गखरेजा, कपिल नाचानी, शैलेश कटारिया, हनी कस्तूरी, विनोद वाधवानी, नानक लुंज, जितेन्द्र शिकारपूरी, प्रकाश रूपचंदानी, विक्की राजपाल, राजेश तलदार, संजय खतुरिया, भावेश तलदार, कपिल मनवानी, अनिल नेभनानी, सतीश वाधवानी, हरीश भाटिया, सुमित परियानी, पंकज नागपाल सहित अनेक सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा। समिति ने कहा कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और उनके प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रहेगा।

सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 85,439 पर बंद:निफ्टी भी 78 अंक गिरा; IT सेक्टर के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट

24 न्यूज अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी 5 जनवरी को गिरावट रही। सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 85,439 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट रही, ये 26,250 के स्तर पर बंद हुआ।

हालांकि निफ्टी ने आज कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड हाई बनाया, इसने 26,373 के स्तर को छुआ। आज IT और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

दिल्ली दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद–शरजील इमाम को जमानत से किया इनकार, पाँच आरोपियों को सशर्त राहत, उमर–शरजील एक साल तक नई याचिका नहीं दे सकेंगे

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामलों में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों अगले एक वर्ष तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे। वहीं, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—इन पाँच आरोपियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। ये सभी आरोपी पाँच साल तीन महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस कॉमन आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें UAPA के तहत जमानत से इनकार किया गया था।

कोर्ट का संतुलनः अनुच्छेद 21 बनाम UAPA

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) संवैधानिक व्यवस्था में विशेष स्थान रखता है और ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि UAPA एक विशेष कानून है, जिसमें धारा 43D(5) के तहत जमानत के सामान्य मानकों से अलग परीक्षण लागू होता है। अदालत के अनुसार, राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में केवल देरी को जमानत का 'तुरुप का पत्ता' नहीं बनाया जा सकता।

फैसले की प्रमुख बातें

हाईकोर्ट के कॉमन आदेश के खिलाफ अपीलें थीं; लंबी हिरासत और अनुच्छेद 21 पर दलीलें दी गईं। अदालत ने कहा कि यह संविधान बनाम कानून की अमूर्त तुलना नहीं, बल्कि कानून के ढांचे के भीतर न्यायिक परीक्षण है। UAPA 43D(5) जमानत के सामान्य प्रावधानों से अलग है, पर यह न्यायिक जांच को खत्म नहीं करता। UAPA की धारा 15 के अनुसार आतंकवादी कृत्य में आतंक फैलाने का इरादा और उससे उत्पन्न/संभावित परिणाम महत्वपूर्ण हैं। सभी आरोपी एक जैसी स्थिति में नहीं; व्यक्तिगत मूल्यांकन जरूरी। प्री-ट्रायल हिरासत लंबी होने पर राज्य को अनुच्छेद 21 के तहत औचित्य बताना होगा। ट्रायल कोर्ट को तेजी से सुनवाई और संरक्षित गवाहों की बिना देरी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश।

बचाव पक्षः "दंगे भड़काने का ठोस सबूत नहीं" आरोपियों ने दलील दी कि ट्रायल शुरू होने में लगातार देरी हो रही है, वे पाँच साल से अधिक समय से जेल में हैं और दंगे भड़काने से जुड़े ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए।

हाईकोर्ट का रुख और पुलिस का विरोध

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उमर और शरजील की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर प्रतीत होती है; उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण और भीड़ उकसाने के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत का विरोध किया और कहा कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपी स्वयं जिम्मेदार हैं; सहयोग मिलने पर दो साल में ट्रायल पूरा किया जा सकता है।

2020 दंगेः पृष्ठभूमि

फरवरी 2020 में CAA–NRC विरोध के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। 53 मौतें, 250+ घायल, और 750+ FIR दर्ज हुई थीं।

शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 (दंगों से छह सप्ताह पहले) और उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का दावाः "पूर्व नियोजित साजिश"

पुलिस के मुताबिक, दंगे अचानक नहीं, बल्कि पैन-इंडिया साजिश का हिस्सा थे—उद्देश्य 'सत्ता परिवर्तन' और 'आर्थिक दबाव' बनाना। आरोप है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के समय हिंसा कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने की योजना थी। जांच में व्हाट्सएप ग्रुप्स, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) और जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का भी उल्लेख किया गया है।

सोना 1386 बढ़कर 1.36 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ:चांदी 2,513 महंगी होकर 2.37 लाख किलो बिक रही

24 न्यूज अपडेट

सोने-चांदी के दाम में आज यानी 5 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,386 रुपए बढ़कर 1,36,168 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,34,782 रुपए पर था।

वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,513 रुपए बढ़कर 2,37,063 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,34,550 रुपए किलो थी। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को सोना 1,38,161 रुपए और चांदी 2,43,483 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी।

संपादकीय : जवाबदेही के बजाय

इंदौर में पेयजल दूषित होने की वजह से कई लोगों की मौत के बाद राहत के तौर पर सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ रस्मी औपचारिकताएं पूरी करना इस समस्या का हल हो सकता है ! सबसे जरूरी था कि इस घटना के बाद निचले स्तर के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के समांतर शीर्ष स्तर पर बरती गई लापरवाही के लिए भी जिम्मेदारी तय की जाती। मगर ऐसा लगता है कि इसे किसी सामान्य हादसे की शक्ल में देखा जा रहा है। वरना क्या कारण है कि इतने गंभीर मामले के बाद भी सरकार के रवैये में एक अफसोसनाक उदासीनता दिख रही है। इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय यहां के एक मंत्री सवालों को जिस तरह बेमानी बता रहे थे, उसमें एक विचित्र उपेक्षाभाव था । अव्वल तो पेयजल जैसी सबसे बुनियादी जरूरत के पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर सरकार अपनी ओर से सजग रहती, लेकिन इसके बजाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है कि प्रभावित इलाके में पीने के पानी के अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएं। इस घटना से फिर यही जाहिर हुआ है कि महज हादसा या चुक मानी जाने वाली कई घटनाएं अक्सर अधिकारियों की अदूरदर्शिता, लंबे समय से बरती जाने वाली लापरवाही और कई बार जानबूझ कर की गई उपेक्षा का नतीजा होती हैं इंदौर के जिस इलाके में पेयजल दूषित होने की घटना सामने आई, क्या ऐसा अचानक हो गया होगा ? अगर फिलहाल आई खबरों पर ही भरोसा किया जाए कि पानी की आपूर्ति वाले पाइप में गंदे नाले का पानी मिल गया, तो इस पर निगरानी रखना किसकी जिम्मेदारी है? एक बार पेयजल की पाइप बिछा देने के बाद उसमें पानी आ रहा है या नहीं या फिर वह पीने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, इसकी नियमित जांच करने, गड़बड़ियों की निगरानी करने का दायित्व किस पर है ? अगर संबंधित महकमे में निचले स्तर पर तैनात कर्मचारी लापरवाही बरत रहे थे, तो इसका ध्यान रखना किसका काम था ? इस गंभीर घटना के बाद सवाल उठने और कठघरे में खड़ा किए जाने के बाद जहां सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर सख्त संदेश देने वाली कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां उसके मंत्री संवेदनहीन, अवांछित और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे थे। अफसोस की बात यह भी है कि इस समूचे मामले में केंद्र सरकार ने एक तरह से विचित्र चुप्पी साधे रखी और उसकी ओर से कुछ नहीं किया गया। जबकि पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के लिए तमगा जीतने वाले इंदौर में दुषित पेयजल से जिस तरह की त्रासद घटना सामने आई, वैसे में पीड़ित परिवारों से लेकर देश भर के आम लोग यह उम्मीद करते हैं कि इसकी गंभीरता के मद्देनजर केंद्र सरकार दखल देगी। दरअसल, ऐसे नाजुक मौकों पर सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि सरकार आम लोगों के प्रति संवेदनशील दिखे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने का भरोसा दे । मगर कम से कम इस मामले में सच यह है कि लोगों का सरकार पर से भरोसा बुरी तरह टूटा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पर 'हर घर नल जल योजना के तहत सभी नागरिकों को पीने का स्वच्छ और शुद्ध पानी मुहैया कराने के दावे किए जाते रहे हैं। मगर पेयजल को लोगों तक पहुंचाने के रास्ते में अगर किसी भी वजह से ऐसी लापरवाही होती है कि उससे लोगों की जान पर खतरा आ जाए, तो ऐसे दावों को किस तरह देखा जाएगा।

दोहरे मानदंड

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पिछले कुछ समय से बने तनाव का नतीजा अब भयावह रूप में सामने आ रहा है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस शुक्रवार देर रात अमेरिका के हवाई हमलों से दहल उठी। इस अभियान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया गया है। इस हमले की वजह मादक पदार्थों की तस्करी बताई जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद को सीमा पार बढ़ावा दे रहा है। मगर सवाल है कि क्या कोई शक्तिशाली देश इस तरह की समस्या से निपटने के लिए किसी छोटे और कमजोर राष्ट्र पर हमला कर सकता है? वह भी अमेरिका जैसा देश, जहां के राष्ट्रपति दुनिया के विभिन्न देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते नहीं थकते हैं और खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का दावेदार घोषित कर चुके हों ! ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई को दोहरा मानदंड नहीं, तो और क्या कहा जाएगा। दरअसल, अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। यहां इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि अमेरिका ने वर्षों पहले इराक पर यह आरोप लगाकर हमला किया था कि वहां रासायनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है। मगर इसका कोई स्टीक प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है। जहां तक वेनेजुएला से अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी की बात है, तो इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत या फिर अंतरराष्ट्रीय अदालत के जरिए सुलझाया जा सकता है वेनेजुएला ने तो पिछले सप्ताह अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत के लिए हामी भी भर दी थी। फिर क्या वजह रही कि अमेरिका वार्ता के बजाय हमले को चुना, इस कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग अमेरिका के इस हमले को वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के इरादे से जोड़कर भी देख रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी पिछले दिनों एक साक्षात्कार में इस ओर इशारा किया था कि अमेरिका उनके देश में तख्ता पलट कर वहां के विशाल तेल भंडार तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहता है।

अलसाई सुबह और में कोहरे में लिपटी लेकसिटी, सब कुछ थम सा गया

24 न्यूज अपडेट

लेकसिटी उदयपुर की सुबह आज कोहरे की चादर ओढ़े हुए जागी। सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा शहर पर इस कदर तरह छाया कि कुछ घंटों के लिए पूरा शहर ही मानो अदृश्य हो गया। ठंडी बयार के बीच कोहरे को देख लगा मानों बादल सैर करने सड़कों पर निकल आए हों। खेतों में लहलहाती फसलों से बातें करने पहुंच गए हों। कोहरे की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि हर किसी का दिल खुश हो गया। दृश्यता इतनी कम थी कि सड़कें धुंध में खो गईं, और वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। झीलों के किनारे से लेकर पहाड़ों और तालाबों के नजारों तक सब कुछ नजारा और भी रहस्यमय रहा। दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग रुक-रुक कर आज के कोहरे और बढ़ती सर्दी पर चर्चा करते नजर आए। उदयपुर शहर का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी हवा के साथ नमी ने ठिठुरन को और गहरा कर दिया। उदयपुर संभाग के अन्य जिलों में भी ठंड ने अपना रंग दिखाया। राजसमंद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, प्रतापगढ़ में 8.1 डिग्री, बांसवाड़ा में 9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरे का असर कुछ समय तक बना रह सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने और नागरिकों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है।

यूरिया संकट पर किसानों का अनूठा व्यंग्यात्मक विरोध, गधों को जामुन खिलाकर 'खाद' का शोक मनाया

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर में यूरिया खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने मंगलवार को एक अनूठा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि विभाग कार्यालय के बाहर किसानों ने गधों को फूलों की माला पहनाई, उन्हें गुलाब जामुन खिलाकर मुंह मीठा कराया और खाद के बैग को कुर्सी पर रखकर उसकी तस्वीर बनाते हुए सांकेतिक शोक व्यक्त किया। किसानों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उसी तरह विलाप किया, जैसे किसी के निधन पर किया जाता है। किसानों का कहना था कि यह प्रदर्शन सरकार और प्रशासन का ध्यान खाद संकट की गंभीरता की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया। प्रदर्शन के दौरान गधों को माला पहनाकर नारेबाजी भी की गई और खाद के बैग को 'मृत' मानते हुए उसकी प्रतीकात्मक तेरहवीं जैसा दृश्य रचा गया।

POS मशीन नियमों की खुलेआम अनदेखी

किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक पॉश मशीन से प्रति किसान अधिकतम 10 बैग यूरिया दिए जा सकते हैं, लेकिन दुकानदार जानबूझकर मशीन से पर्ची नहीं दे रहे। इससे किसान को यह तक पता नहीं चल पा रहा कि उसके नाम से कितने बैग निकाले जा चुके हैं। कई मामलों में किसान को सिर्फ 2 बैग दिए जा रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में 10 बैग का उठाव दिखाया जा रहा है। किसानों के मोबाइल पर वितरण से संबंधित संदेश भी नहीं पहुंच रहे।

277 रुपए की खाद 500 में बेची जा रही

मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि खाद की सबसे ज्यादा जरूरत के समय खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। सरकार द्वारा तय 277 रुपए प्रति बैग की जगह किसानों से 450 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। पटेल ने आरोप लगाया कि यह सब अधिकारियों की शह पर हो रहा है, जिन्हें कमीशन से मतलब है, न कि किसानों की परेशानी से। उन्होंने बताया कि लाइसेंस प्राप्त गोदामों में जहां 150 बैग पहुंचने चाहिए, वहां केवल 100 बैग ही दिए जा रहे हैं, जबकि शेष खाद अन्यत्र भेजकर कालाबाजारी की जा रही है। सरकार के पास कृषि भूमि, फसल चक्र और संभावित उत्पादन का पूरा डेटा होने के बावजूद हर रबी और खरीफ सीजन में यही संकट क्यों खड़ा होता है, यह एक बड़ा सवाल है।

अधिकारियों तक पहुंच रहा कमीशन

समिति के सह-संयोजक मदनलाल डांगी ने कहा कि खाद की कालाबाजारी बिना प्रशासनिक संरक्षण के संभव नहीं है। अफसरों तक कमीशन पहुंच रहा है और किसान खून के आंसू पीने को मजबूर हैं। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों पर सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

राशन वितरण की तर्ज पर खाद वितरण की मांग

किसान संघर्ष समिति ने मांग की कि खाद वितरण के लिए भी राशन वितरण जैसी पारदर्शी समिति बनाई जाए। हर खरीद पर पॉश मशीन से अनिवार्य रूप से स्लिप दी जाए और किसानों को उनकी कृषि भूमि के आधार पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शन के बाद किसानों ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा को ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि इससे पहले करीब 20 दिन पूर्व जिला कलेक्टर और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

अवैध खनन के विरूद्ध अभियान, मेसेनरी स्टोन से भरे दो ट्रैक्टर -ट्रॉली जब्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अरावली विस्तार वाले जिलों में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उदयपुर जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खनि अभियंता आसिफ अंसारी ने बताया कि पुलिस थाना ओगणा क्षेत्र में सोमवार को अवैध खनन कर ले जाया जा रहा पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। ट्रैक्टर को डिटेन कर इसकी सूचना खान विभाग को दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसी प्रकार संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा डबोक क्षेत्र में अवैध निर्गमन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध मेसेनरी स्टोन जब्त की गई। जब्त वाहन को पुलिस थाना डबोक की सुपुर्दगी में दिया गया है। अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय मेला-त्योहारों पर अवकाश घोषित

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले में वर्ष 2026 के दौरान आयोजित होने वाले प्रमुख स्थानीय मेला-त्योहारों के अवसर पर अवकाश घोषित किए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.6(1) सा.प्र.वि./6/2024-4471 दिनांक 16 अक्टूबर 2025 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर 16 जुलाई 2026, गुरुवार को मध्यान्ह पश्चात आधे दिवस का स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी तरह हरियाली अमावस्या पर 12 अगस्त 2026, बुधवार को भी मध्यान्ह पश्चात आधे दिवस का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं जलझूलनी एकादशी के पर्व पर 22 सितंबर 2026, मंगलवार को जिले में पूर्ण दिवस का स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश कलेण्डर वर्ष 2026 (ग्रेगोरियन), ई. शक संवत 1947-1948 के अंतर्गत घोषित किए गए हैं और जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों एवं संबंधित विभागों पर लागू होंगे। आदेश जिला कलक्टर नमित मेहता की ओर से जारी किया गया है।

प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सचखंड दरबार से 10 दिनों तक प्रभात फेरियां, आज भव्य आतिशबाजी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रकाश पर्व की पावन खुशियों के बीच सिख कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा सचखंड दरबार से लगातार दस दिनों तक प्रभात फेरियां निकाली गईं। प्रभात फेरियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुरबाणी के मधुर कीर्तन और शबदों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। प्रभात फेरियां गुरुद्वारा परिसर से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्रों से गुजरती हुई पुनः गुरुद्वारे में संपन्न हुईं। श्रद्धालु हाथों में निशान साहिब और दीपक लिए, गुरबाणी का जाप करते हुए चल रहे थे। सुबह के शांत वातावरण में कीर्तन की स्वर लहरियों ने लोगों के मन में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा सचखंड दरबार को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जिससे रात्रि के समय गुरुद्वारा की भव्यता और भी निखर कर सामने आई। श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जनवरी को आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे प्रकाश पर्व की खुशियों को और उल्लासपूर्ण बनाया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं, जिनमें स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया।

NH-8 पर रफ्तार का कहरः ट्रक–कंटेनर की भीषण भिड़ंत, दोनों वाहन पलटे

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर जिले में नेशनल हाईवे-8 सोमवार सुबह उस समय दहल उठा, जब खरपीना गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भारी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गए। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, जिनमें ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अचानक कंटेनर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रक डिवाइडर से भिड़ते हुए पलट गया, जिससे उसका केबिन बुरी तरह चकनाचूर हो गया। ट्रक में लदे लोहे के पाइप सड़क पर चारों ओर बिखर गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं कंटेनर भी संतुलन खो बैठा और करीब 100 फीट तक घिसटते हुए पलट गया। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर यातायात थम गया। मौके पर मौजूद राहगीरों और वाहन चालकों ने मानवता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कुछ समय के लिए हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर गोवर्धनविलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण घना कोहरा माना जा रहा है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। इसी कारण चालक समय रहते सामने चल रहे वाहन को नहीं देख सका। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रक और कंटेनर को सड़क से हटवाया, वहीं बिखरे लोहे के पाइप हटाकर मार्ग को साफ कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को धीरे-धीरे बहाल किया गया।

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह बुधवार को, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मुख्य अतिथि, 90 शोधार्थियों को मिलेगी पीएचडी उपाधि

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाएगा। समारोह दोपहर 12:15 बजे प्रारंभ होगा। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे।

दीक्षांत समारोह को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया।

राज्यपाल करेंगे विद्यार्थियों को सम्मानित

प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने बताया कि समारोह में पूर्व कुलपति एवं राज्यपाल राजस्थान के उच्च शिक्षा सलाहकार प्रो. कैलाश सोडाणी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारु, गरिमामय और समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।

सात हजार से अधिक अतिथियों की उपस्थिति

विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड़ ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विद्या प्रचारिणी सभा के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं शहर के गणमान्य नागरिकों सहित सात हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति रहने की संभावना है। समारोह के लिए विशाल और सुव्यवस्थित पांडाल तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

90 पीएचडी, 47 गोल्ड मेडल और 2025 डिग्री अवार्ड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. एन.एन. सिंह ने जानकारी दी कि दीक्षांत समारोह में

90 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 47 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, तथा 2025 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि समारोह से एक दिन पूर्व मंगलवार शाम 4 बजे अकादमिक प्रक्रिया की रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जिससे सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके।

बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद

तैयारी बैठक में संयुक्त मंत्री राजेन्द्र सिंह ताणा, वित्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही, कार्य समिति सदस्य डॉ. युवराज सिंह राठौड़, अध्यक्ष प्रो. चेतन सिंह, अधिष्ठाता प्रो. रेणु राठौड़, प्रो. प्रेम सिंह रावलोत सहित संस्थान के समस्त डीन एवं डायरेक्टर उपस्थित रहे।

ऑनलाइन ठगी का संगठित गिरोह बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार, 46 मोबाइल, 42 सिम, 36 एटीएम कार्ड, लैपटॉप बरामद

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए पुलिस थाना सुखेर ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री योगेश गोयल के निर्देशानुसार साइबर ठगों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर एक संगठित ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश ओझा एवं वृत्ताधिकारी नगर पश्चिम श्री राजेश यादव के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी सुखेर श्री रविन्द्र चारण के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई।

मुखबिर की सूचना पर दबिश, ठगी का पूरा सेटअप बरामद

3 जनवरी 2026 को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम ने सोनारिया, लखावली स्थित एक मकान पर दबिश दी। मौके से चार युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से 02 लेपटॉप, 46 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 42 सिम कार्ड, 36 एटीएम कार्ड, 16 बैंक पासबुक, 09 चेकबुक और वाई-फाई राउटर बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग व्यक्तियों से कमीशन पर बैंक खाते खरीदते, फिर उन्हीं खातों को आगे ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन और अवैध धन हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल करते थे। यह गिरोह सुनियोजित तरीके से खाते खरीदने-बेचने का संगठित नेटवर्क चला रहा था।

ऐसे रचते थे ठगी का जाल

पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों सौरभ उपाध्याय और सुमित चंदेल के साथ मिलकर आम लोगों को झांसे में लेते, उनके खातों का दुरुपयोग करते और हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन हासिल करते थे। इस तरह ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध को अंजाम देकर मोटी रकम कमाई जा रही थी।

इन धाराओं में मामला दर्ज

थाना सुखेर में प्रकरण संख्या 08/2026 के तहत धारा 318(4), 316(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 66 व 66D आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों और वित्तीय नेटवर्क को लेकर अग्रिम अनुसंधान जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त

विशाल यादव पुत्र जितेन्द्र सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी पटेल नगर विस्तार, थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा विजयसिंह सिसोदिया पुत्र गोपालसिंह, उम्र 20 वर्ष निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर, थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा मोहम्मद परवेज खान पुत्र बाबु खान, उम्र 25 वर्ष निवासी लेबर कॉलोनी, थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा मनीष राठौर पुत्र दिनेश राठौर, उम्र 24 वर्ष निवासी महावीर नगर, थर्ड टीचर्स कॉलोनी, थाना महावीर नगर, जिला कोटा।

कार्रवाई करने वाली टीम

श्री रविन्द्र चारण — थानाधिकारी, सुखेर
श्री खुमाणसिंह — सहायक उप निरीक्षक
श्री रामकुंवार — हेड कांस्टेबल 355
श्री ओमप्रकाश — कांस्टेबल 2049
श्री वीरेंद्रपाल सिंह — कांस्टेबल 3012
श्री राजेन्द्र सिंह — कांस्टेबल 892
श्री सुमेरराम — कांस्टेबल 1456
श्री चेतनदास — कांस्टेबल 330
श्री कानसिंह — चालक कांस्टेबल 1001

चित्तौड़गढ़ में पुलिस हाजिर है मगर हाजिरी कहां है?? क्या बिना उपस्थिति होता है वेतन जारी??

रिपोर्ट- जयवंत भैरवियां

24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़। सूचना के अधिकार के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिले के सभी पुलिस थानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है और न तो बायोमेट्रिक व्यवस्था है। न ही कोई उपस्थिति रजिस्टर ही है। इसके बावजूद पुलिस कर्मियों का वेतन समय पर जारी हो रहा है। यह खबर न केवल सामान्य जनता के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या सरकार बिना काम के वेतन देकर करोड़ों का आर्थिक नुकसान कर रही है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, यह तो खुद पुलिस ने RTI में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आरटीआई में खुलासा किया कि जिले के किसी भी थाने में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाती और बायोमेट्रिक प्रणाली भी लागू नहीं है। याने पुलिस हाजिर ता है हर जगह हर समय पर मगर हाजिरी के अते पते नहीं हैं। सीटीएनएस में केवल एक कार्मिक गिनता है उपस्थिति आवेदन में 11 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ और प्रथम अपील अधिकारी जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस विभाग ने अपने तर्क में कहा कि सीटीएनएस (Centralized Training & Notification System) पर हाजरी दर्ज की जाती है, लेकिन इसमें केवल एक कर्मी द्वारा गिनती की जाती है, जबकि अन्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर शामिल नहीं होते। विशेषज्ञों के अनुसार यह तरीका पूरी तरह से अविश्वसनीय जैसा है। जब हाजिरी का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, तो वेतन कैसे बनता है। ऐसे में विभाग की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ड्यूटी पर उपस्थिति तय कैसे हो पाती है।

पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र

RTI खुलासे के बाद जागरूक पत्रकार जयवंत भेरविया ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और मांग की है कि चित्तौड़गढ़ पुलिस विभाग में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विधि विपरीत जारी वेतन की वसूली और भविष्य में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह खुलासा केवल चित्तौड़गढ़ तक सीमित नहीं है। राजस्थान के कई जिलों में पुलिस विभाग की इसी तरह की लापरवाही का अंदेशा है। सरकार ने पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजरी और सख्त नियम लागू किए हैं। लेकिन पुलिस विभाग को इन नियमों से अलग आखिर क्यों रखा गया है। सवाल ये नहीं कि पुलिस में उपस्थिति होती है या नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि पुलिसकर्मी हमेशा तय घंटों से कहीं अधिक घंटे काम करते हैं व कई कई बार तो महीनों तक बिना अवकाश के काम करते हैं मगर उस काम का कोई तो बायो मेट्रिक या रजिस्टर आदि में अंकन होना ही चाहिए। यह मामला प्रशासनिक सुस्ती का भी उदाहरण है। जवाबदेही के अभाव का भी सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस गंभीर मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी, या पुलिस विभाग के बिना हाजरी वेतन का यह मॉडल यूँ ही चलता रहेगा। RTI एक्टिविस्ट के अनुसार, यदि तत्काल सुधार नहीं किया गया तो यह प्रणाली भ्रष्टाचार और आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे सकती है।

परिवहन विभाग ने जारी की नवीन नंबर सीरीज, आरजे 27 एफसी 0001 से 9999 तक पंजीयन शुरू

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 5 जनवरी। परिवहन विभाग ने प्राइवेट सर्विस व्हीकल के लिए नई पंजीयन संख्या सीरीज आरजे 27 एफसी 0001 से 9999 तक आरंभ करने की घोषणा की है। इच्छुक वाहन मालिक अब अग्रिम पंजीयन के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी मुकेश कुमार डाड ने बताया कि नवीन पंजीयन प्रक्रिया के लिए सभी आवेदन केवल ई-ऑक्शन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। निलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर जाकर स्वयं लॉगिन आईडी बनानी होगी। इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी पोर्टल के मेन्यू में उपलब्ध है।

सुगम रेल संचालनः उदयपुर सिटी-खजुराहो रेलसेवा जल्द रीस्टोर

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर जारी तकनीकी कार्य के कारण पूर्व में आंशिक रूप से रद्द की गई उदयपुर सिटी-खजुराहो रेलसेवा अब अपने सामान्य संचालन में लौट रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को राहत देते हुए समय सारणी अनुसार रेल सेवा संचालन की जानकारी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण ने बताया कि तकनीकी कारणों से रद्द की गई सेवाओं को पुनः शुरू किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 19666, उदयपुर सिटी-खजुराहो रेलसेवा 5 जनवरी 2026 से उदयपुर सिटी से अपने निर्धारित मार्ग एवं समय सारणी अनुसार संचालित होगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 19665, खजुराहो-उदयपुर सिटी रेलसेवा 7 जनवरी 2026 से खजुराहो से निर्धारित समय के अनुसार सेवा प्रदान करेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सामयिक सूचना और प्लेटफार्म विवरण की पुष्टि अवश्य करें। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफार्म पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ सेक्शन में रेलवे ट्रैफिक नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन मुख्य सेवाओं पर इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उदयपुर जिला ओलंपिक संघ की वार्षिक साधारण सभा संपन्न, नए पदाधिकारी और संरक्षक नियुक्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर जिला ओलंपिक संघ की वार्षिक साधारण सभा कल होटल वीरगढ़ फॉर्म में संपन्न हुई। इस अवसर पर संघ का संशोधित संविधान प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। संघ सचिव जालमचंद जैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह मुकेश जैन को नया सचिव चुना गया। वहीं, संयुक्त सचिव के रिक्त पद पर जिला तीरंदाजी संघ के सचिव गिरधारी सिंह चौहान को सह सचिव मनोनीत किया गया। सभा में भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान प्रदेश भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक प्रमोद सामर को संरक्षक और जालमचंद जैन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। सभा में एथलिट आयोग, एथिक्स आयोग, आंतरिक शिकायत समिति सहित कई अन्य समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। उदयपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। संघ से मान्यता प्राप्त खेल संघों के लिए वार्षिक एफिलिएशन फीस 1,000 रुपए तय की गई। संरक्षक प्रमोद सामर के नेतृत्व में खेल संघों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही जिला कलेक्टर और उदयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव से मुलाकात कर खेलों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करेगा। सभा में प्रमुख रूप से उपस्थित थेः जिला ओलंपिक संघ के चेयरमैन दिनेश श्रीमाली, जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चुंडावत, राजस्थान कयाकिंग एवं कैनॉइंग संघ के अध्यक्ष भगवान वैष्णव और सचिव दिलीप सिंह चौहान, भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष प्रमोद सामर, जिला एथलेटिक संघ के सचिव भूपेंद्र सिंह चौहान, जिला तीरंदाजी संघ के सचिव गिरधारी सिंह चौहान, जिला कबड्डी संघ के सचिव मुकेश जैन और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खनूजा जिला शतरंज संघ के प्रवीण कोठारी, जिला कराटे संघ के विक्रम सिंह सहगल, जिला स्केटिंग संघ के मनजीत सिंह, जिला तैराकी संघ से चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला पावरलिफ्टिंग संघ से देवेन्द्र साहूभाजपा नेता भंवर सिंह पंवार सहित कई खेल संघों के पदाधिकारी।RTI एक्टिविस्ट के अनुसार, यदि तत्काल सुधार नहीं किया गया तो यह प्रणाली भ्रष्टाचार और आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे सकती है।

जगन्नाथ स्वामी की जयकारों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा रवाना

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही निःशुल्क तीर्थ यात्रा 2025 के तहत वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन आज, 5 जनवरी 2026 को राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई। हरी झंडी दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में बिठाया गया। इस अवसर पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, निवर्तमान उपमहापौर एवं भाजपा महामंत्री पारस सिंघवी, साथ ही देवीलाल सालवी, पंकज बोराना, तुषार मेहता, खुशबू मालवीय, राजमल चित्तौड़ा, अतिरिक्त आयुक्त गीतेश मालवीय, सहायक आयुक्त जतिन गांधी और ऋषभदेव दीपिका मेघवाल उपस्थित थे। स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों ने सेल्फी प्वाइंट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के साथ फोटो खिंचवाने का आनंद लिया। ट्रेन में राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से 517 वरिष्ठ नागरिक सवार हुए, वहीं चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से 189, और कोटा रेलवे स्टेशन से 264 यात्री ट्रेन में शामिल होंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करवाए जाएंगे, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे। ट्रेन का प्रभारी मनीष जोशी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झाड़ोल को बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष पहली बार एसी ट्रेन की सुविधा प्रदान की गई है, जबकि पूर्व में नॉन-एसी ट्रेन संचालित होती थी। कुल 970 वरिष्ठ नागरिक और ट्रेन प्रभारी, मेडिकल टीम तथा अनुरक्षक सहित 30 सदस्य स्टाफ, यानी कुल 1000 यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान चाय, नाश्ता, भोजन, गंतव्य पर आवास और दर्शन जैसी सभी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। तीर्थ यात्रा 10 जनवरी को वापस उदयपुर लौट कर आएगी। इसके बाद अगली निःशुल्क ट्रेन यात्रा 13 जनवरी को अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रवाना होगी।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

हाथी वाला पार्क : भ्रष्टाचार का जीता-जागता मॉन्युमेंट

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर में विकास के नाम पर खड़ा यह ढांचा अब भ्रष्टाचार का जीता-जागता मॉन्युमेंट बन चुका है। पहले यहां पर हाथी वाला पार्क हुआ करता था लेकिन अचानक किसी की फितूर के चलते यहां अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी गई। यह पार्किंग जनता की सुविधा नहीं बल्कि जनता के पैसे से चलने वाला एटीएम बन गई है जो किसको बार बार लाभ दे रहा है यह कहने की जरूरत नहीं हैं। भ्रष्टाचारियों को आप अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह पार्किंग शुरू से ही गलत डिजाइन और घटिया निर्माण के कारण चर्चा में रही। इंजीनियरों को पता था यहां पानी भरेगा मगर उनको तो ठेकेदारों के माध्यम से अपनी जेबें भरनी थी, इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो राफ्ट फाउंडेशन ही नहीं लिया गया, जबकि ऐसी अंडरग्राउंड संरचना में यह अनिवार्य था। इसकी दीवारें डैम की तरह मजबूत और वाटरप्रूफ होनी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा यह है कि पार्किंग में लगातार पानी भरता भर रहा है। स्थिति यह है कि पानी निकालने के लिए बरसों से 24 घंटे मोटर चला कर पानी नाली में बहाना पड़ रहा हैं।

वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क लेने वाला निगम खुद कर कहा लाखों लीटर पानी बर्बाद

एक तरफ नगर निगम जनता से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल रहा है, तो दूसरी तरफ यही नगर निगम सालों से लाखों हजारों लीटर पानी खुद बर्बाद कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, निगम के भ्रष्ट अफसर और इसे चलाने वाले महाभ्रष्ट नेता हैं। जनता के पैसों से बनी पार्किंग में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल पानी में डूब चुका है। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण चोरी हो चुके हैं।

यह रहे भ्रष्टाचार के सबूत, कौन है राजनेता जो है इसका जिम्मेदार

भ्रष्टाचार की हद देखिए— आज भी पार्किंग के कई हिस्सों में पीपल के पेड़ उग आए हैं, जो साफ दिखाता है कि निर्माण कितना घटिया था। यह छिपी हुई बात नहीं है कि इसी घटिया निर्माण के चलते पहले ठेकेदार का करीब 4 करोड़ रुपये का भुगतान रोका गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक सुपर पावर की सांठगांठ से वही भुगतान करवा दिया गया। याने पैसा उस सुपर पावर की जेब में भी गया। सबसे चौंकाने वाला मामला डिफ्लेक्शन टेस्ट का है। जिस टेस्ट की लागत मात्र 10 हजार रुपये थी, उसके लिए नगर निगम ने 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया। कोई देखने वाला नहीं, लूट सके तो लूट वाला आलम है।

नगर निगम के पास इंजीनियरों की पूरी फौज होने के बावजूद इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण होना सीधे-सीधे संगठित भ्रष्टाचार की कहानी कहता है।

आंकड़ों की जुबानी, भ्रष्टाचार की कहानी

अब बात आंकड़ों की— पिछले एक साल में इस पार्किंग से कुल आय हुई सिर्फ 2.16 लाख रुपये। जबकि इसी अवधि में रखरखाव और संचालन पर खर्च किए गए 4.86 लाख रुपये। यानि नगर निगम को इस पार्किंग से 2.70 लाख रुपये का सीधा घाटा हुआ।

यात्रियों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पार्किंग में पानी भरने से

वाहनों को नुकसान हो रहा है और आम जनता परेशान है। नगर निगम आयुक्त ने शहरभर में नालों की सफाई का अभियान शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद अपने ही दफतर में हाथी वाला पार्क की पार्किंग में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं करवा सके।

हाईकोर्ट को बताना है, इसलिए पार्क बनाना है

अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट में जो PIL लगी थी, वह पार्क को री-स्टोर करने के लिए थी, ना कि पार्किंग की छत पर नया पार्क बनाने के लिए। इसके बावजूद हाईकोर्ट में दंड से बचने के लिए पार्किंग की छत पर डेढ़ से दो करोड़ रुपये खर्च कर नया पार्क बनाया जा रहा है। घटिया बेसमेंट पर बने पार्क का क्या हश्र होगा ये अभी से पता चल रहा है। भविष्य में इसे भी तोड़ना ही पड़ेगा। यानि पहले पार्किंग बनाने में 14 करोड़ रुपये बर्बाद, अब पार्क बनाने में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा, और आगे चलकर नतीजा शून्य मिलने वाला है। विशेषज्ञों के मुताबिक,यह पूरा मॉडल कमाई कम – घाटा ज्यादा और भ्रष्टाचार ज्यादा – जवाबदेही शून्य का क्लासिक उदाहरण है। अब सवाल सीधा है— क्या दोषी इंजीनियरों, अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी? या फिर हाथी वाला पार्क की यह पार्किंग हमेशा के लिए भ्रष्टाचार का स्मारक बनकर खड़ा रहेगा।

इधर परीक्षा उधर शोर, कैसे चले किसी का जोर, प्रशासन ध्यान दो इस ओर...

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान न हो, इस चिंता के चलते अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के प्रांत संगठन मंत्री राकेश पालीवाल और जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को विशेष ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में संगठन के जिला मंत्री नारायण पंचोली, विष्णु जोशी और अनिल टांक भी मौजूद रहे। ज्ञापन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में बजने वाले तेज आवाज वाले ध्वनि यंत्रों जैसे डीजे और लाउडस्पीकर के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा आने की बात कही गई। प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इन यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया जाए, ताकि परीक्षार्थियों का ध्यान भटके नहीं और वे परीक्षा की तैयारी पूरी एकाग्रता के साथ कर सकें। ज्ञापन सौंपते हुए अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रशासन इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और विद्यार्थियों के हित को सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन कराएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि बोर्ड परीक्षाओं की अवधि में शोर नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, परीक्षा के समय छात्र एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीजे और लाउडस्पीकर से होने वाले अत्यधिक शोर से न केवल ध्यान भटकता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में प्रशासन का यह कदम छात्रों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है।

उदयपुर में जर्जर स्कूलों का मुद्दा ठंडे बस्ते में, संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। झालावाड़ जिले में जुलाई माह में एक विद्यालय की जर्जर कक्षा गिरने से नौ बच्चों की मृत्यु के बाद, प्रदेशभर के जर्जर स्कूलों की स्थिति पर अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर परमार के नेतृत्व में संगठन ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर जिले के 480 जर्जर विद्यालय भवनों और 5,415 जर्जर कक्षा कक्षों के शीघ्र निर्माण और मरम्मत की मांग की। संगठन के जिला महामंत्री कमलेश शर्मा ने बताया कि इन जर्जर भवनों के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के हित में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ निर्माण कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ स्कूल ग्रामीण और गरीब इलाकों में स्थित हैं, जहां स्थानीय भामाशाहों से धन जुटाने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। संघ ने राज्य सरकार से अपील की कि शिक्षा के नाम पर केवल घोषणाएँ करने की बजाय वास्तविक निर्माण कार्य तेजी से शुरू कराया जाए, ताकि बच्चों को गर्मी, बारिश और शीतलहर से सुरक्षा मिल सके। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश जैन, प्रदेश संगठन मंत्री भेरूलाल कलाल, बड़गांव ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह भाटी, गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम बेरवा, ओम प्रकाश बिश्नोई, गजेंद्र शर्मा, राजेश व्यास, राजेश शर्मा सहित कई संगठन कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

क्रायो प्रेसिपिटेट से सटीक, सुरक्षित और किफायती इलाज की दिशा में बड़ा कदम

सरल ब्लड सेंटर में कार्यशाला, दक्षिणी राजस्थान का पहला ब्लड बैंक बना आधुनिक रक्त कम्पोनेन्ट तकनीक से लैस

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। रक्त चिकित्सा के क्षेत्र में रोगियों को सटीक, सुरक्षित और कम खर्च में प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में उदयपुर स्थित सरल ब्लड सेंटर ने एक अहम पहल की है। रोगियों के उपचार में रक्त के आवश्यक कम्पोनेन्ट्स के वैज्ञानिक उपयोग को लेकर "क्रायो प्रेसिपिटेट" की बढ़ती उपयोगिता विषय पर सरल ब्लड सेंटर सभागार में शहर के प्रख्यात चिकित्सकों की उपस्थिति में एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य रक्त आधान की परंपरागत व्यवस्था में सुधार करते हुए रोगी को केवल वही रक्त कम्पोनेन्ट उपलब्ध कराना था, जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता हो। आमतौर पर संपूर्ण प्लाज्मा (एफएफपी) चढ़ाए जाने से जहां रोगी को अपेक्षित लाभ कम और जोखिम अधिक होता है, वहीं क्रायो प्रेसिपिटेट तकनीक से उपचार अधिक सटीक, सुरक्षित और किफायती बनता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरल संस्था के मानद सचिव सीए (डॉ) श्याम एस. सिंघवी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि विगत 17 वर्षों से अधिक समय से संचालित सरल ब्लड सेंटर को दक्षिणी राजस्थान के प्रथम ब्लड सेंटर के रूप में "क्रायो प्रेसिपिटेट" सहित सभी प्रकार के रक्त कम्पोनेन्ट्स तैयार करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा "रेमी मेक" कंपनी का अत्याधुनिक थाविंग बाथ उपकरण स्थापित किया गया है, जिससे रक्त के प्रत्येक कम्पोनेन्ट को अलग कर जरूरतमंद रोगी तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बावजूद अब तक क्रायो प्रेसिपिटेट का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिसे लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई।

ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ नरेंद्र मोगरा ने पीपीटी के माध्यम से क्रायो प्रेसिपिटेट की चिकित्सकीय उपयोगिता को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इसमें फाइब्रिनोजन, कॉग्यूलेशन फैक्टर VIII व XIII, वॉन विलेब्रांड फैक्टर और फाइब्रोनेक्टिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि अनावश्यक प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। क्रायो प्रेसिपिटेट की मात्रा मात्र 15 मिलीलीटर होने से शरीर पर अतिरिक्त द्रव भार नहीं पड़ता। इसका उपयोग अत्यधिक रक्तस्राव, डीआईसी, सर्जिकल व एक्सीडेंटल ट्रॉमा तथा किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों में अत्यंत लाभकारी है। डॉ मोगरा ने बताया कि इसके विपरीत एफएफपी की 180 मिलीलीटर मात्रा बच्चों व वृद्ध मरीजों में सर्कुलेटरी ओवरलोड का खतरा बढ़ा देती है। क्रायो प्रेसिपिटेट न केवल अपेक्षाकृत कम लागत वाला है, बल्कि इसकी कम मात्रा के कारण एबीओ अनुकूलता की आवश्यकता भी नहीं रहती, जिससे आपातकालीन उपचार में तेजी आती है। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे रोगियों के हित में क्रायो प्रेसिपिटेट को प्राथमिकता दें। कार्यशाला में वरिष्ठ चिकित्सकों डॉ बी.एस. बंब, रक्त चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ संजय प्रकाश, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ सचिन जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ एन.के. जोशी, डॉ कल्पेश चौधरी एवं डॉ विनोद पोरवाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए क्रायो प्रेसिपिटेट के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया तथा सरल ब्लड सेंटर के इस नवाचार की सराहना की। इस अवसर पर सरल संस्था के सह-सचिव संयम सिंघवी ने बताया कि सेवारत कर्मियों का दीर्घकालीन जुड़ाव संस्था की पहचान रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि लंबे समय से ब्लड सेंटर में सेवाएं दे रहे चिकित्साधिकारी डॉ सुरेश डांगी एवं डॉ प्रांशु शर्मा को अपरिहार्य कारणों से विलग होने पर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यशाला में उपस्थित चिकित्सकों ने एकमत से कहा कि उदयपुर के अस्पतालों के सभी डॉक्टर और सर्जन यदि आपसी समन्वय के साथ क्रायो प्रेसिपिटेट का सही समय पर उपयोग करें, तो रोगियों को कम खर्च में सटीक और सुरक्षित उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।